बजट 2026: ऋण की मात्रा नहीं, उसकी गुणवत्ता सुधारने पर जोर

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 ऐसे समय में आया है, जब ग्रामीण भारत और छोटे उद्यमी सिर्फ विकास ही नहीं, बल्कि स्थिरता भी चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाएँ यह संकेत देती हैं कि अब ध्यान सिर्फ ऋण की पहुँच व्यापक करने पर नहीं, बल्कि आय के मजबूत आधार तैयार करने पर भी है। एक ऐसे ऋणदाता के नजरिए से, जो आवास ग्राहकों, छोटे कारोबारियों और कृषि से जुड़े उधारकताओं के साथ मिलकर काम करता है, इस बजट की सबसे अहम् बात जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार करने पर दिया गया जोर है। ग्रामीण ऋण व्यवस्था की एक बड़ी सच्चाई आय में उतार-चढ़ाव है। कृषि, इससे जुड़े अन्य कार्य और सूक्ष्म उद्यम उत्पादक क्षेत्र जरूर हैं, लेकिन ये मौसम, बाजार के दामों में बदलाव और भुगतान में देरी जैसी स्थितियों से प्रभावित भी होते हैं। ऐसे में, डिजिटल कृषि सलाह, सिंचाई सहायता, बेहतर बाजार संपर्क और तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म पर लगातार दिया जा रहा जोर काफी अहम् है। सही जानकारी और मजबूत वैल्यू चेन केवल उत्पादन नहीं बढ़ाते, बल्कि आय को

उमेश अरोड़ा, हेड- इमर्जिंग बिजनेस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

अधिक स्थिर और अनुमानित भी बनाते हैं। ऋणदाताओं के लिए यह स्थिरता पुनर्भुगतान व्यवहार को मजबूत करती है और लंबे समय में पोर्टफोलियो की गुणवत्ता बेहतर बनाती है। एमएसएमई के लिए देयकों के फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क्स को मजबूत करने और भुगतान अनुशासन सुधारने पर दिया गया जोर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे अनुभव में कई छोटे उद्यम मूल रूप से सक्षम होते हैं, लेकिन भुगतान में देरी के कारण नकदी का दबाव उनके कामकाज पर असर डालता है। यदि देयकों की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बने, तो बिना अतिरिक्त ऋण बोझ बढ़ाए भी इस दबाव को कम किया जा सकता है। समय के साथ इससे एमएसएमई क्षेत्र में अधिक स्वस्थ ऋण चक्र विकसित होने में मदद मिलेगी।

एक और धीमा लेकिन अहम बदलाव औपचारिक व्यवस्था की ओर बढ़ता कदम है। डिजिटल भुगतान का रिकॉर्ड, जीएसटी से जुड़ा डेटा, भूमि अभिलेखों में सुधार और प्लेटफॉर्म आधारित कारोबार का विस्तार, ये सब मिलकर लोगों की स्पष्ट वित्तीय प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। उधारकताओं के लिए इससे उचित दरों पर औपचारिक ऋण तक पहुँच आसान होती है। वहीं ऋणदाताओं को आकलन और जोखिम निर्धारण में ज्यादा स्पष्टता मिलती है। कई मायनों में अब डेटा पारंपरिक जमानत का पूरक बनता जा रहा है। हालाँकि, ऋण विस्तार संतुलित रहना चाहिए। नीतिगत सहयोग और बेहतर व्यावसायिक माहौल से हाउसिंग, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में ऋण की माँग बढ़ सकती है। लेकिन, सतत विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि आय का आकलन यथार्थवादी हो और क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार ऋण मूल्यांकन किया जाए।